

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 29 संख्या: 334

प्रभात

अजमेर, शनिवार 5 जुलाई, 2025

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

‘लंगड़े बारात के घोड़े, “रेस हॉर्स” बनना चाहते हैं’

राहुल की इस शिकायत से कई पुराने नेता अति नाखुश, पर बेबस हैं

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 जुलाई। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के उन जनरलों (वरिष्ठ नेताओं), जिन्होंने वर्षों तक वफादारी और समर्पण के साथ पार्टी की सेवा की है, के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें “लंगड़े घोड़े” कहा, जो अब बूढ़े, बीमार और संगठन के लिए बेकार हो चुके हैं, जिन्हें अब हटा कर “चरागाह” में भेज दिया जाना चाहिए। इस पर पार्टी के अंदर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई।

पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस टिप्पणी से न केवल आहत हैं, बल्कि गुस्से और दुख से भी पर उठे हैं। पार्टी से लंबे समय से जुड़े मझोले स्तर के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की भाषा और शब्दों के चयन को घमंड से भरा तथा एक नेता के लिए अनुपयुक्त करार दिया।

एक अन्य कार्यकर्ता ने यह पूछ लिया कि क्या वे (राहुल) यही शब्द अपनी माँ और बहन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक ने रिटायरमेंट ले लिया है और दूसरी को कुछ वर्षों से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी

■ पर इतना जरूर हुआ है कि दबी जुबान से सवाल भी पूछे जाने लगे हैं, राहुल गांधी के बारे में।

■ जब राहुल, पुराने “अनफिट” नेताओं के रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सोनिया गांधी का नाम लेने लगे हैं लोग, क्योंकि वे काफी असें से बीमार चल रही हैं, पर आखिरी निर्णय में उनकी काफी चलती है।

■ जिन लोगों को राहुल रिटायर देखना चाहते हैं, उनमें कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेन्द्र हुड्डा का नाम ऊपर ही ऊपर है।

■ जो, अपने आप रिटायर कर दिये गये उनमें टॉप में नाम हैं जनार्दन द्विवेदी का, जनार्दन द्विवेदी एक तरह से सोनिया गांधी के “मेंटर” जैसे थे, पर, उन्होंने अकारण एक स्टेटमेंट दे दिया कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि दोनों भाई-बहन में प्रियंका ज्यादा उपयुक्त हैं, राजनीति के लिए। इस वक्तव्य के बाद वो कांग्रेस के रंगमंच से गायब से ही हो गये थे।

■ इसी प्रकार गहलोत, हाईकमान के खिलाफ बगावत करने के कारण, “साइड लाइन्ड” हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद, “एंट्री” नहीं पा सके हैं।

की कमान संभाली है, पार्टी में नेताओं की तीन श्रेणियां उभर कर सामने आईं

हैं: वे, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है, वे जिन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया

है, और वे, जो पार्टी के संचालन के तौर-तरीकों से नाखुश होकर पार्टी छोड़ गये हैं।

सबसे पहला नाम, जिसकी चर्चा पार्टी में होती है, वह है प्रियंका गांधी का। वे हाईकमान का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें एक तरह से निष्क्रिय कर दिया है। वे कहने को तो एआईसीसी की महासचिव हैं, लेकिन उनके पास न कोई विभाग है, न कोई जिम्मेवारी। उनके करीबी लोग पार्टी पदों से हटा दिए गए हैं और अन्य लोग भी उनसे दूर हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि प्रियंका उनके करियर में कोई मदद नहीं कर सकती।

ऐसे नेताओं की सूची लंबी है। जनार्दन द्विवेदी, जिन्हें सोनिया गांधी का राजनीतिक गुरु तक माना जाता था, ने एक बार सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि प्रियंका गांधी राजनीति में राहुल से अधिक उपयुक्त हैं तथा वे राजनीति में अच्छा काम कर सकती हैं। उसी दिन से द्विवेदी का पतन शुरू हो गया और वे पूरी तरह हाशिए पर चले गए।

अशोक गहलोत, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तथा तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या पर सुनवाई जुलाई के अंत में

जयपुर, 4 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों के आत्महत्या करने से जुड़े मामले में सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में रखी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंगान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अवलत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समान मामला लंबित बताया जा रहा है। वहां 17 जुलाई को

■ सुप्रीम कोर्ट का इस बिंदु पर रुख स्पष्ट होने तक हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली।

सुनवाई होनी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च शिक्षा को लेकर मामला सुन रहा है या कोचिंग छात्रों के बिंदु पर प्रकरण की सुनवाई कर रहा है। ऐसे में 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद इसकी स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। इसलिए प्रकरण की सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में करना उचित होगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भगवान को न्याय में देखें जजों में नहीं’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत नई दिल्ली-
नई दिल्ली, 4 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोगों से यह सलाह दी कि वे भगवान को न्यायाधीशों में न ढूंढ़े बल्कि न्याय में ढूंढ़े। जस्टिस एमएम सुंद्रेश ने यह टिप्पणी उस समय की, जब एक वकील ने कोर्ट में कहा, “जज हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं।” न्यायमूर्ति सुंद्रेश ने स्पष्ट किया कि न्यायधीश सिर्फ विनम्र सेवक होते हैं और उन्होंने कहा, “हम में भगवान की न तलाश करें, न्याय में भगवान की तलाश करें। हम केवल विनम्र सेवक हैं।”

■ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंद्रेश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान उस समय यह टिप्पणी की जब वकील ने कहा कि जज हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं।

यह टिप्पणी एक वकील द्वारा एक नोटिस पर आपत्ति जताए जाने के बाद आई, जिसमें यह दावा किया गया था कि वकीलों ने न्यायधीशों को फिक्स किया था। वकील ने उस नोटिस को “अपमानजनक” बताया। जस्टिस सुंद्रेश ने कहा, कृपया भावुक न हों। जज के तौर पर हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।। पिछले साल, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी यह स्पष्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात हाईकोर्ट्स में 36 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने दो दिन तक 54 उम्मीदवारों का इटरव्यू लेकर यह नियुक्तियां की हैं

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 जुलाई। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में दो दिन तक 54 उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार किया। उसके बाद 7 उच्च न्यायालयों में जजों के रूप में पदोन्नति के लिए रिपोर्ट 36 मामलों को मंजूरी दी। इसके साथ ही देशभर के 25 उच्च न्यायालयों में 1,122 स्वीकृत पदों के मुकाबले 371 रिक्तियों में से कुल 90 पद भर दिए गए हैं।

जिन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए नाम मंजूर किए गए हैं, उनमें दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पटना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान सहित कई न्यायालय शामिल हैं। कोलीजियम के प्रस्ताव के

अमेरिका व भारत के बीच टैरिफ समझौते की सम्भावना लगभग समाप्त

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाशिंगटन में पत्रकारों से कहा, भारत “डैड लाइन” के दबाव में वाणिज्य समझौते नहीं करता है

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 जुलाई। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता, जिसे अमेरिका द्वारा 9 जुलाई से शुरू किए जाने वाले “रैसिप्रोकल टैरिफ” से पहले अंतिम रूप दिया जाना था, अब फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल के आरंभ के तुरंत बाद, डॉनल्ड ट्रंप ने विश्व के विभिन्न देशों पर “रैसिप्रोकल टैरिफ” लगाने की घोषणा की थी, जिसमें भारत पर भी 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था, जो 9 जुलाई से लागू होना है।

वाशिंगटन में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पत्रकारों को दिया गया यह बयान, कि भारत किसी डेडलाइन के दबाव में व्यापार समझौते नहीं करता, इस बात का संकेत है कि यह बातचीत अब लम्बे समय तक चल सकती है। भारत यह संदेश देना चाहता था कि उसे दबाव डालकर किसी समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत सरकार के सर्वोच्च स्तर

■ जैसा की विदित ही है, दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प ने घोषणा की थी, कि 9 जुलाई से अमेरिका भारत से आयातित सभी सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा।

■ टैरिफ समझौता वार्ता टूटने का आभास इस बात से भी मिलता है, कि, भारत ने डब्ल्यु.टी.ओ. में कहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा, एक तरफा निर्णय है, और गलत है।

■ अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी थी, कि “रेअर अर्थ” खनिज की सप्लाई अमेरिका को तुरन्त शुरू करे अन्यथा कई सख्त आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने पड़ेंगे। इसके बाद चीन ने निर्यात शुरू कर दिया था।

■ अमेरिका, भारत से भी यह उम्मीद कर रहा था। पर, पिछले दिनों पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसीफ मुनीर के भड़काऊ भाषणों के बाद पहलगाम नरसंहार हुआ, तथा अमेरिका ने मुनीर को भारी सम्मान दिया उनकी की यात्रा के दौरान।

से स्वीकृति के बिना सार्वजनिक रूप से इस रुख की घोषणा नहीं की जा सकती थी।

इस बीच, भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के डिस्प्यूट ट्रिब्युनल में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुंभलगढ़ जिले में मोहरर्म जुलूस की अनुमति का विवाद गहराया

किले में प्रवेश बंद, सैकड़ों पर्यटक वापस लौटे, बाज़ार पूरा बंद रहा

उदयपुर, 4 जुलाई। (कास)। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में मोहरर्म के जुलूस की अनुमति को लेकर विवाद अब और अधिक गहराता जा रहा है। शुक्रवार को भी हालात यथावत ही बने रहे। किले में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, बाजार आज भी बंद रहे और स्थानीय बसों का संचालन भी पूरी तरह ठप्प है। विवाद के कारण बाहर से आने वाले पर्यटक भी किला नहीं देख पा रहे हैं जिससे पर्यटन प्रभावित हुआ है और स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। हिंदू संघर्ष समिति ने मोहरर्म के जुलूस को दी गई अनुमति को लेकर विरोध जताते हुए आज भी प्रदर्शन किया गया।

समिति का कहना है कि जब पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार शाम पांच बजे के बाद किले में प्रवेश की अनुमति नहीं होती तो मोहरर्म के ताजियों को शाम को किले में जाने की अनुमति कैसे दी गई। समिति ने इस पर

■ हिन्दू संघर्ष समिति का कहना है कि जब पुरातत्व के नियमों के अनुसार, शाम पाँच बजे के बाद किले में प्रवेश की अनुमति नहीं होती तो मोहरर्म के ताजियों को शाम को किले में जाने की अनुमति कैसे दी गई। समिति ने इसे धार्मिक आयोजनों पर दोहरा मापदंड बताया।

कड़ी आपत्ति जताई और धार्मिक आयोजनों में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। गुरुवार को हिंदू संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग कुंभलगढ़ बस स्टैंड पर एकत्र हुए और किले की ओर मार्च किया। रास्ते में टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए इस दौरान किले में प्रवेश पर रोक को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तोखी नोकझोंक भी हुई। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कुंभलगढ़ में भारी पुलिस बल तैनात किया है।

इस बीच कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र

सिंह राठौड़ भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे विवाद की जड़ पुरातत्व विभाग की गलती है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले केलवाड़ा में भी मोहरर्म के रूट को बदला गया था तो यहां भी ऐसा किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में समुचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इधर हिंदू संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि जब तक मोहरर्म जुलूस की अनुमति वापस नहीं ली जाती तब तक कुंभलगढ़ का बाजार अनिश्चितकाल के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सब लैफ्टिनेंट आस्था पूनिया नौ सेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनीं

नयी दिल्ली, 04 जुलाई। सब लैफ्टिनेंट आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। नौसेना ने शुक्रवार को बताया कि विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक एयर बेस पर दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के पूरा होने के बाद गुरुवार को उन्हें यह

■ बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के बाद उन्हें यह गौरव मिला। ज्ञातव्य है कि आस्था पूनिया व अतुल कुमार को इस कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए “विंग्स ऑफ गोल्ड” सम्मान भी मिला है।

गौरव हासिल हुआ। इस कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लैफ्टिनेंट अतुल कुमार और सब लैफ्टिनेंट आस्था पूनिया को सहायक नौसेना प्रमुख (वायु) रियर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘चीन, पाकिस्तान को “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान, भारत के हवाई हमले व सेना के “मूवमेंट” की सारी जानकारी तुरंत भेज रहा था’

भारतीय सेना के डिप्टी चीफ, ले.जनरल राहुल आर. सिंह ने स्पष्ट जानकारी दी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 जुलाई। देश के डेपूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (केपेबिलिटी डवलपमेंट एंड सस्टेनेन्स) लैफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने आज यह स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव ऑपरेशनल डेटा प्रदान किया, जिससे भारत की रक्षा और रणनीतिक योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं।

भारत की रक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण गैप को उजागर करते हुए, उप सेनाध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत तीन दुश्मनों से लड़ रहा था। “हमारे पास एक सीमा थी और दो दुश्मन थे, वास्तव में तो तीन थे। पाकिस्तान तो सामने था चीन उसे सभी संभव सहायता

■ सिंह के अनुसार, उस समय हम तीन दुश्मनों, चीन, पाकिस्तान व टर्की से एक साथ लड़ रहे थे तथा पाकिस्तान का अस्सी प्रतिशत युद्ध का सामान चीन में निर्मित था और चीन द्वारा सप्लाई किया गया था।

■ पाकिस्तान, चीन व टर्की यह जानते थे कि जैसे ही युद्ध लंबा खिंचा और उसका स्तर, तकनीकी दृष्टि से और जटिल हुआ, भारत का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा और पाकिस्तान उसके मुकाबले में टिक नहीं पायेगा।

■ अतः, जैसे ही युद्ध “एस्कलेट” होता दिखा, चीन ने पाकिस्तान को सलाह दी, आत्मसमर्पण करो व संधि की कोशिश करो। इसलिए, पाकिस्तान के डी.जी.एम.ओ. ने भारत के डी.जी.एम.ओ. को फोन किया और युद्ध विराम की अर्ज़ी दी।

■ ले.जनरल सिंह के अनुसार, भारत के लिये यह जानना अत्यन्त जरूरी है कि उसके हवाई जहाजों, मिसाइल्स आदि की जानकारी चीन तक कैसे पहुँच रही थी, भारत के सुरक्षातंत्र में इतना बड़ा “गैप” क्यों था और कहीं से आया था।

■ ले.जनरल सिंह के अनुसार, भारत ने भी पाकिस्तान की युद्ध विराम की अर्ज़ी इसलिये स्वीकार कर ली, क्योंकि, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य तो पूरा हो गया था। पाकिस्तान समझ गया था कि भारत अब दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत प्रभाव से आतंकवादी हमले का अवश्य जवाब देगा।

प्रदान कर रहा था। पाकिस्तान का 81 प्रतिशत सैन्य हार्डवेयर चीनी है, चीन अपने हथियारों का परीक्षण दूसरे

हथियारों के खिलाफ करना चाहता है, तो यह संघर्ष उसके लिए एक “लाइव” प्रयोगशाला की तरह था।”

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसी सी-फिक्की) के एक कार्यक्रम में बोलते

हुए, लैफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा, “जब डीजीएमओ स्तर की वार्ता चल रही थी, तब पाकिस्तान को चीन से हमारी

सैन्य तैनाती के बारे में इनपुट मिल रहे थे। इस मसले पर हमें तेजी से कदम उठाने और उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, पिछले पांच वर्षों में, पाकिस्तान का 81 प्रतिशत सैन्य हार्डवेयर चीन का ही रहा है।”

सिंह ने कहा कि चीन की मदद से ही पाकिस्तान भारत की गतिविधियों को तुरंत ट्रैक कर सका, जिससे ऑपरेशन का रूप बदल गया और भारत की रक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण झोल (गैप) का पता चला, जिसे जल्दी ही ठीक करने की आवश्यकता है।

सिंह ने यह भी कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान को उन्नत किस्म के ड्रोन प्रदान किए। “तुर्की ने भी पाकिस्तान को विशिष्ट प्रकार का सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने पाकिस्तान को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन से दो करोड़ मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। यह राष्ट्रीय मसला है इसलिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।

मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है।

पार्टी सूत्रों ने आज यहां बताया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK